proximately 1200 hotel beds as follows:

Place	Bed capacity
1. Santa Cruz Airport, Bombay (Transit Hotel)	100
2. Dum Dum Airport, Calcutta (Transit Hotel)	100
3. Varanasi	200
4. Bangalore	200
5. Juhu Sea Beach, Bombay	200
6. Panaji (Goa)	100
7. Srinagar	100
8. Kovalam Sea Beach (Trivandrum)	100

The hotels will generally confirm to a uniform pattern providing central airconditioning, restaurant, swimming pool, a shopping arcade facilities.

The construction of an annexe to the Ashoka Hotel in New Delhi which is a Public Sector project, to provide additional 300 beds by February, 1968 is under way.

The Janpath Hotels Ltd., also a Public Sector Undertaking have plans to build Hotel Akbar at the corner of Ashoka Road an Janpath at a cost of Rs. 2.77 crores with 300 beds, subject to availability of funds.

Establishment of a Hotel in collaboration with Hiltons Hotels Corporation

468. **Shri C. C. Desai:**
Shri R. Barua:

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken on the proposal to establish a Hotel in India in collaboration with some Indian firm and the Hiltons Hotels Corporation of U.S.A.; and

(b) if so, the main terms of the collaboration?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). No, Sir. The draft agreement for collaboration between Messrs. Shiv Sagar Estates, Bombay and Hilton Hotels Corporation of U.S.A. is under examination.

दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

469. श्री राम चरण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में किन-किन तारीखों को दिल्ली दुग्ध योजना के दूध तथा अन्य उत्पादों के मूल्य बढ़ाये गये और प्रत्येक अवसर पर मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना को अपने उत्पादों की बिक्री से बहुत लाभ होता है जिसका बहुत बड़ा भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में खर्च हो जाता है; और

(ग) उत्तर प्रदेश हरियाना और राजस्थान के दूधियों से दिल्ली दुग्ध योजना किस भाव पर दूध खरीदती है और दिल्ली की जनता को किस भाव पर बेचा जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) एक विवरण रखी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या L.T. 217/67].

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्तर प्रदेश, हरियाना तथा राजस्थान के राज्यों से भैंस तथा गाय के

दूध की खरीद के वर्तमान दर (ठेकेदारों की कमीशन निकाल कर) निम्नलिखित हैं :—

राज्य	6.5 प्रतिशत चर्बी सहित भैंस के दूध के लिए मूल कीमत	गाय के दूध की मूल कीमत
(1) यू०पी०	77.50 रुपये प्रति क्विंटल	. .
(2) हरियाना		
(1) करनाल जिला	69.93रु० प्रति क्विंटल	. .
(2) अन्य क्षेत्र	77.50रु० प्रति क्विंटल	77.50रुपये प्रति क्विंटल
(3) राजस्थान	—	55.00रुपये प्रति क्विंटल

दिल्ली दुग्ध योजना से बेचे गये विभिन्न प्रकार के दूध का बिक्री मूल्य निम्नलिखित है :—

	प्रति लिटर
1. मानकीकृत दूध (8.5 प्रतिशत एस०एन० एफ०, 5 प्रतिशत चर्बी)	84 पैसे
2. गाय का दूध (न्यूनतम 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ० 3.5 प्रतिशत चर्बी)	84 पैसे
3. टोन्ड दूध (8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ०, 3 प्रतिशत चर्बी)	54 पैसे
4. डबल टोन्ड दूध (9 प्रतिशत एस० एन० एफ०, 1.5 प्रतिशत चर्बी)	40 पैसे

कृषि इंजीनियर तथा विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कृषि विशेषज्ञ

470. श्री राम चरण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि इंजीनियर तथा विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त कृषि विशेषज्ञ, अलग-अलग कितने हैं ;

(ख) उन में से कितने व्यक्ति कृषि-कार्य में लगे हुए हैं ;

(ग) क्या बेरोजगार कृषि इंजीनियरों के लिए कृषि कार्य सम्बन्धी रोजगार की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "डायरेक्टरी आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पर्सनल इन इंडिया (1964)" के अनुसार 1964 तक भारत में 325 कृषि इंजीनियर थे। नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पिछले 2 वर्षों की अवधि में कृषि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों से लगभग 200 कृषि स्नातक निकले हैं और इस प्रकार ऐसे इंजीनियरों की संख्या 5 5 हो जाती है। इन में से 56 विदेशों से प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

(ख) हमारे ज्ञान के अनुसार सभी प्रशिक्षित कृषि इंजीनियर कृषि या कृषि से सम्बन्धित उद्योगों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) यद्यपि बेकार कृषि इंजीनियरों के लिए कृषि कार्य सम्बन्धी रोजगार की व्यवस्था करने की कोई विशेष योजना नहीं है फिर भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने ऐसी अनेक योजनायें तैयार की हैं जिनकी